FATF 2025 रिपोर्ट: पाकिस्तान की राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत

UPSC प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन पेपर 2

समाचार में क्यों?

- जुलाई 2025 में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने अपनी रिपोर्ट "कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क्स" जारी की। पहली बार, FATF ने "राज्य प्रायोजन" को आतंकवादी वित्तपोषण को एक स्रोत के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक मान्यता है।
- यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता है, जिसने लगातार पाकिस्तान की भूमिका को सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने और आतंकवादी नेटवर्कों को वित्त पोषित करने के रूप में उजागर किया है।

FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के बारे में

FATF क्या है?

- FATF एक अंतर-सरकारी संस्था है, जिसे 1989 में G7 समिट में पेरिस में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य वैश्विक मानकों की स्थापना करना और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों(WMD) के वित्तपोषण के खिलाफ प्रभावी उपायों को बढ़ावा देना है।

मुख्य तथ्य:

- मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
- सचिवालय: OECD द्वारा आयोजित
- सदस्य: 39 (37 देश + EU और GCC क्षेत्रीय संगठन)
- भारत की सदस्यता: 2010 से पूर्ण सदस्य

FATF वॉच लिस्ट:

- 1. ग्रे लिस्ट: वे देश जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों के लिए वृद्धि की निगरानी में होते हैं।
- 2. ब्लैक लिस्ट: वे देश जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में गैर-सहयोगी होते हैं, और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं।

मुख्य प्रकाशन:

- 1. FATF सिफारिशें (40 सिफारिशें): वैश्विक एंटी- मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण मानक।
- 2. म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स: देशों का मूल्यांकन।
- 3. नेशनल रिस्क असेसमेंट्स (NRAs): घरेलू मनी लॉन्ड्रिंग/ आतंकी वित्तपोषण जोखिम।
- 4. टाइपोलॉजी रिपोर्ट्स: जैसे, "कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क्स" (2025)।

संबद्ध संस्थाएँ:

- एशिया पैसिफिक ग्रुप
- यूरेशियन ग्रुप
- मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका FATF
- अन्य वैश्विक क्षेत्रीय संगठन।

भारत का महत्व:

- भारत ने FATF प्लेटफार्मों का प्रभावी उपयोग किया है, विशेष रूप से पाकिस्तान के राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने में, खासकर LeT (लश्कर-ए-तैयबा) और JeM (जैश-ए-मोहम्मद) जैसे समूहों के संदर्भ में। भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट (2018-2022) में डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पाकिस्तान पर आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव पड़ा।

FATF 2025 रिपोर्ट के प्रमुख मुख्य बिंदु

1. राज्य प्रायोजन की पहली बार स्वीकृति:

- FATF ने औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया कि कुछ सरकारें आतंकवादी संगठनों को वित्तीय, लॉजिस्टिक, और प्रशिक्षण समर्थन प्रदान करती हैं। इसे अब वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा, और वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर जोखिम के रूप में चिन्हित किया गया है।

2. निष्कर्षों के लिए वैश्विक समर्थन:

- कई वैश्विक प्रतिनिधिमंडल ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और सदस्य देशों के खुफिया जानकारी के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत किए।

3. पाकिस्तान का विशिष्ट संदर्भ:

- रिपोर्ट ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण-पूर्व एशिया, और पूर्वी अफ्रीका को आतंकवादी वित्तपोषण के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना। यह अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन (2024) के निष्कर्षों को भी दर्शाता है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है।

व्यापक प्रभाव

1. वैश्विक वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव:

- बैंकों और वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) में, अब पाकिस्तान से जुड़े लेन-देन पर अधिक सतर्कता से काम करेंगे।
- इसका परिणाम यह हो सकता है कि पाकिस्तान को वित्तीय अलगाव का सामना करना पड़े और उसे वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के लिए उच्च कॉम्प्लायंस (अनुपालन) का बोझ उठाना पड़े, जिससे ड्यू डिलिजेंस (सावधानीपूर्वक जांच) की आवश्यकताएँ बढ़ जाएंगी।

2. भूराजनीतिक महत्व:

- यह रिपोर्ट भारत की वैश्विक कथा को पाकिस्तान के राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से प्रस्तुत करती है।
- यह उन देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाती है जो पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से आतंकवाद वित्तपोषण राज्य के रूप में मान्यता देने में हिचकिचा रहे हैं।

राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के रूपों की पहचान

- FATF की रिपोर्ट में राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के कई रूपों की पहचान की गई, जिनमें शामिल हैं:
- आतंकी समूहों को सीधे वित्तीय सहायता।
- लॉजिस्टिक समर्थन: सुरक्षित आश्रय, हथियारों की आपूर्ति और परिवहन।
- प्रशिक्षण समर्थन: शिविर और विशेषज्ञता साझा करना।
- अवैध व्यापार-आधारित वित्तपोषण: उदाहरण के लिए, ईरान से पाकिस्तान तक ड्रग तस्करी मार्ग।

भारत का FATF 2025 रिपोर्ट में योगदान

- भारत, फ्रांस और UN काउंटर-टेररिज़्म कमेटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट के मसौदे में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत ने आतंकवाद वित्तपोषण जोखिमों में राज्य अभिनेताओं को स्पष्ट रूप से शामिल करने का समर्थन किया, जो वैश्विक आतंकवाद वित्तपोषण प्रयासों में एक रणनीतिक कूटनीतिक सफलता है।

भारत की सुरक्षा और कूटनीति के लिए महत्व

पहलू	प्रभाव
आतंकवाद विरोधी कूटनीति	पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन पर भारत की दीर्घकालिक स्थिति को मान्यता देती है।
पाकिस्तान का वित्तीय अलगाव	पाकिस्तान के लेन-देन पर वैश्विक निगरानी को बढ़ाती है, जिससे उसके वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
FATF की विश्वसनीयता	FATF के राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को एक वैश्विक वित्तीय खतरे के रूप में स्वीकृति को दर्शाता है।
वैश्विक जोखिम मूल्यांकन	भविष्य में वैश्विक नेशनल रिस्क असेसमेंट्स (NRAs) में राज्य अभिनेताओं को आतंकवाद वित्तपोषण जोखिमों में शामिल किया जाएगा।

निष्कर्ष:

- 2025 की FATF रिपोर्ट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता है। राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए एक खतरे के रूप में औपचारिक रूप से स्वीकार करके, यह वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करती है और उन देशों को अलग-थलग करती है, जैसे पाकिस्तान, जो आतंकवाद को विदेशी नीति के रूप में एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं।
- भारत की प्रोएक्टिव कूटनीति ने वैश्विक आतंकवाद विरोधी मानकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कानून के शासन और जवाबदेही पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की ओर अग्रसर है।

MAINS PYQ :

- Q: वित्तीय क्रियावली कार्य बल (FATF) के वैश्विक प्रयासों पर प्रभाव का मूल्यांकन करें, विशेषकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण से मुकाबला करने में (2021)

PRELIMS PRACTICE QUESTION :

Q: वित्तीय क्रियावली कार्य बल (FATF) की स्थापना किस घटना के दौरान की गई थी?

- (a) G7 समिट, पेरिस, 1989
- (b) संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, न्यू यॉर्क, 1990
- (c) G20 समिट, लंदन, 2008
- (d) ASEAN समिट, जकार्ता, 1997

Q: FATF 2025 रिपोर्ट में राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के किस रूप की पहचान की गई थी?

- (a) आतंकवादी समूहों को सीधे वित्तीय सहायता
- (b) लॉजिस्टिक समर्थन: सुरक्षित आश्रय, हथियार आपूर्ति और परिवहन
- (c) प्रशिक्षण समर्थन: शिविर और विशेषज्ञता साझा करना
- (d) उपरोक्त सभी